(b) if so, how many persons are on that Committe and what are their names and where from they have been drawn;

(c) what are the terms and conditions of that Committee; and

(d) how many meetings of that Committee have been held till date, what business was transacted therein and if no meetings have been held, the reasons therefor and the steps taken to activate that Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIVANCES AND PENSONS (SMT. MARGARET ALVA) (a) to (c) A Joint Cadre Authority for IAS Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories was consituted on 3.4.1989 in accordance with sub-rule (1) of Rule 4 of the All India Services (Joint Cadre) Rules, 1972 for the management of the Cadre. Additional Secretary and Joint Secretary inchadge of U.T. Division, Ministry of Home Affairs and Chief Secretaries of Arunachal Pradesh, Delhi, Goa, Mizoram and Pondicherry are the members of the Joint Cadre Authority. The duties and functions of the Joint Cadre Authority are prescribed in the All India Services (Joint Cadre) Rules, 1972.

(d) This information is not being monitored centrally. Since no complaints have been received about working of the JCAs, need to further activate the JCAs has not been felt.

**ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल में फ्लोराइड का होना**

@3221. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय**
**श्री राम गोपाल यादव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण जल-स्रोतों, विशेषकर पेयजल में फ्लोरा इड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है ;

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1098, 2 मार्च 1994 से स्थानांतरित ।

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है और क्या गांवों के जल स्रोतों मे फ्लोराइड की बढ़ती हुई मात्रा को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और उक्त कायक्रम के क्रियान्वयन हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास) विभाग मे राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 7,342 गांवों के पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड पाया गया था जिन गांवों मे पेयजल स्रोतों में निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड पाया गया है उसका उपचार किया जाता है और उसे वैकल्पिक स्वच्छ स्रोतों अथवा फ्लोराइड दूर करने के संयत्रों की मार्फत निर्धारित सीमा तक लाया जाता है । 106 फिल और ड्रा टाइप तथा 377 फ्लोराइड दूर करने के सयत्रों के साथ लगे हैंडपप अनुमोदित किए गए हैं । संबधित राज्यों के पूर्ण समर्थन और सहयोग से फ्लोराइड दूर करने के विरूद्ध एक स्वास्थ्य शिक्षा कि जन-जागरण अभियान शुरू किया गया है । वैकल्पिक स्वच्छ स्रोतों की मार्फत दूरस्थ स्थान से स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति के लिये काफी बड़ी संख्या में योजनायें अनुमोदित कि गई हैं । यह सतत रूपसे चलने वाला कार्यक्रम है । आठवी पंचवर्षीय योजन के अन्त तक अधिकांश क्षेत्रों मे इस समस्या पर काबू पा लिया जायेगा ।

**Acquisition of Agricultural land by Government**

@@3222. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the area of agricultural land which has been acquired by Government for public purposes during the last three years; and

@@Previously Unstarred Question No. 1728, Transferred from 4th March, 1994.